some technical equipments are known to radiate microwaves and radio frequencies. However, their intensities at the user's location are relatively small and so far no evidence has come forward to establish a casual relationship with cancer. The international standards for manufacture and installation of these equipments also take into account safety aspects.

(b) No. Sir.

(c) Does not arise.

राजस्थान का औद्योगिक विकास

F. 1607. **डा० अबरार अहमद :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है तथा वहां इस समय कौन-कौन से उद्योग बन्द पड़े हैं तथा उन्हें कब तक पुनः चालू कर दिये जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या राजस्थान के रेगिस्तान में पनप सकने वाले कोई कुटीर उद्योगों अथवा लघु उद्योगों के संबंध में सरकार ने कोई अध्ययन किया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या राजस्थान में औद्योगिक विकेन्द्रीकरण के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को कोई सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन) : (क) राजस्थान में औद्योगिक विकास दर बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने दिसम्बर 1990 में एक नयी औद्योगिक नीति अपनायी थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक प्रोत्साहन पैकेज की व्यवस्था थी, जिसमें पूंजीगत निवेश राजसहायता तथा बिक्री कर, चुंगी, मंडी कर आदि में रियायतें व छूट शामिल हैं । नये एककों के लिए, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, एक विन्डो सेवा, औद्योगिक संवर्धन तथा मानव संसाधन विकास ब्यूरों की स्थापना औद्योगीकरण में मदद के लिए आवश्यक है ।

भारतीय रिजर्व बैंक की दिसम्बर, 1988 को समाप्त अवधि की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान राज्य में लघु उद्योग क्षेत्र में रूग्ण एककों की संख्या 11,063 तथा गैर-लघु उद्योग क्षेत्र में रूग्ण एककों की संख्या 45 है । इन एककों के लिए बैंकों, बी आई एफ आर आदि का पुनर्वास संबंधी अध्ययन विभिन्न अवस्थाओं में है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) औद्योगीकरण को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार उद्यमियों को केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में एककों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी में प्राथमिकता, रियायती वित्त, आदि जैसे प्रोत्साहन देती रही है ।

"उद्योग रहित जिलों" में पता लगाए गए विकास केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र सरकार की तत्कालीन सहायता योजना के तहत केन्द्र सरकार ने बाड़मेर, चुरू, जैसलमेर और सिरोही जिलों में विकास केन्द्रों की स्थापना करने का अनुमोदन किया है और केन्द्रीय सहायता के तौर पर 31-3-1990 तक इन जिलों के लिए 191.41 लाख रु० दिए गए हैं ।

नयी विकास केन्द्र योजना के तहत राजस्थान को पांच विकास केन्द्र आबंटित किए गए हैं तथा चार केन्द्रों के स्थापना स्थल का चयन कर लिया गया है और इनकी घोषणा कर दी गयी है । ये हैं : भीलवाड़ा (जिला भीवा भीलवाड़ा) झालवाड़ा (जिला झालावाड़), बीकानेर और आबू (जिला बीकानेर) रोड (जिला सिरोही) । पांचवें केन्द्र के स्थापना-स्थल का अभी चयन किया जाना है । ये विकास केन्द्र उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में आकृष्ट करने के लिए चुम्बक का कार्य करेंगे ।